25 सितम्बर 2017

राष्ट्रपति ट्रम्प की अफ़ग़ानिस्तान नीति: एक मूल्यांकन

डॉ. निहार रंजन दास*

जनवरी 2017 में राष्ट्रपति के सत्ता संभालने के बाद से भविष्य में अफ़ग़ानिस्तान के प्रति अमेरिका (संयुक्त राज्य) की नीति पर छाई अनिश्चतता समाप्त हो गई। पद संभालने के सात महीने पश्चात राष्ट्रपति ट्रम्प ने 21 अगस्त 2017 को दक्षिणी एशिया के प्रति अपने प्रशासन की नीति निर्धारण को अंतिम रूप दिया, जिसमें पूरे क्षेत्र तथा विशेषकर अफ़ग़ानिस्तान के लिए नई नीति की रूपरेखा तैयार की गई।

अफ़ग़ानिस्तान पर लम्बित नीति (देखें संलग्नक 1) ने अफ़ग़ानिस्तान में अमेरिका की लिप्तता से जुड़े सभी कयासों पर विराम लगा दिया। अब तक 800 खरब अमेरिकी डॉलर खर्च करने के बाद भी अफ़ग़ानिस्तान में अमेरिका की लड़ाई समाप्त नहीं हुई है। 2002 से अब तक अफ़ग़ानिस्तान की लड़ाई में अमेरिका के 2,400 से अधिक सैनिक मारे गए हैं और करीब 20,000 घायल हुए हैं। 9/11 हमले के बाद अमेरिका के नेतृत्व में 'आतंक के विरुद्ध लड़ाई,' अफ़ग़ानिस्तान में आतंकवादियों तथा आतंक का नेटवर्क समाप्त करने के अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाई है। उल्टे देश में, विशेषकर 2014 में अधिकतर आईएसएएफ टुकड़ियों की वापसी के बाद आतंकवादी हमलों की संख्या में वृद्धि हुई है।

उल्लेखनीय है कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपना कार्यकाल समाप्त होने के पहले शेष सैनिक टुकड़ियों की वापसी का वादा किया था। लेकिन तालिबान के दोबारा सक्रिय होने के बाद उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया। अक्टूबर 2015 में तालिबान फिर से सक्रिय हो गया और उन्होंने कम से कम 5,500 अमेरिकी सैनिकों के 2016 तक अफ़ग़ानिस्तान में रहने की घोषणा की। जुलाई 2016 में ओबामा ने अपने कार्यकाल के अंत तक अफ़ग़ानिस्तान में 8,400 अमेरिकी सैनिकों को रखने का निर्णय किया।

अफ़ग़ानिस्तान में विभिन्न गुटों की उपस्थिति तथा तालिबान, आईएसआईएस एवं अन्य आतंकवादी गुटों के बढ़ते आतंकवादी हमलों के कारण बातचीत के द्वारा संभावित हल निकालने की समय-सीमा तय नहीं की जा सकी। 2013 से ये मामला गंभीर होता गया और स्थिति बदतर होती गई। इस दौरान कई हमले सुर्खियों में आए, जिनमें बल्ख प्रांत में अफग़ान राष्ट्रीय सेना के 209 शाहीन कॉर्प्स के मुख्यालय पर हमला तथा पिछले छह महीने में काबुल में लगातार कई हमले अफ़ग़ानिस्तानी सुरक्षा की चुनौती के रूप में उभरे हैं। हालांकि तालिबान प्रमुख शहरों पर कब्जा नहीं कर पाया है, लेकिन उसने विभिन्न ज़िलों को अपने प्रभावक्षेत्र में रखने की क्षमता दिखला दी है।

उल्लेखनीय है कि जुलाई 2017 में तालिबान ने पाकटिया, फरयाब तथा घोर प्रांतों के तीन ज़िलों पर कब्जा कर लिया। तीनों प्रांत देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित हैं। पाकटिया मध्य में है, तो फरयाब तथा घोर क्रमश: उत्तरी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में स्थित हैं। (निम्न मानचित्र देखें:)

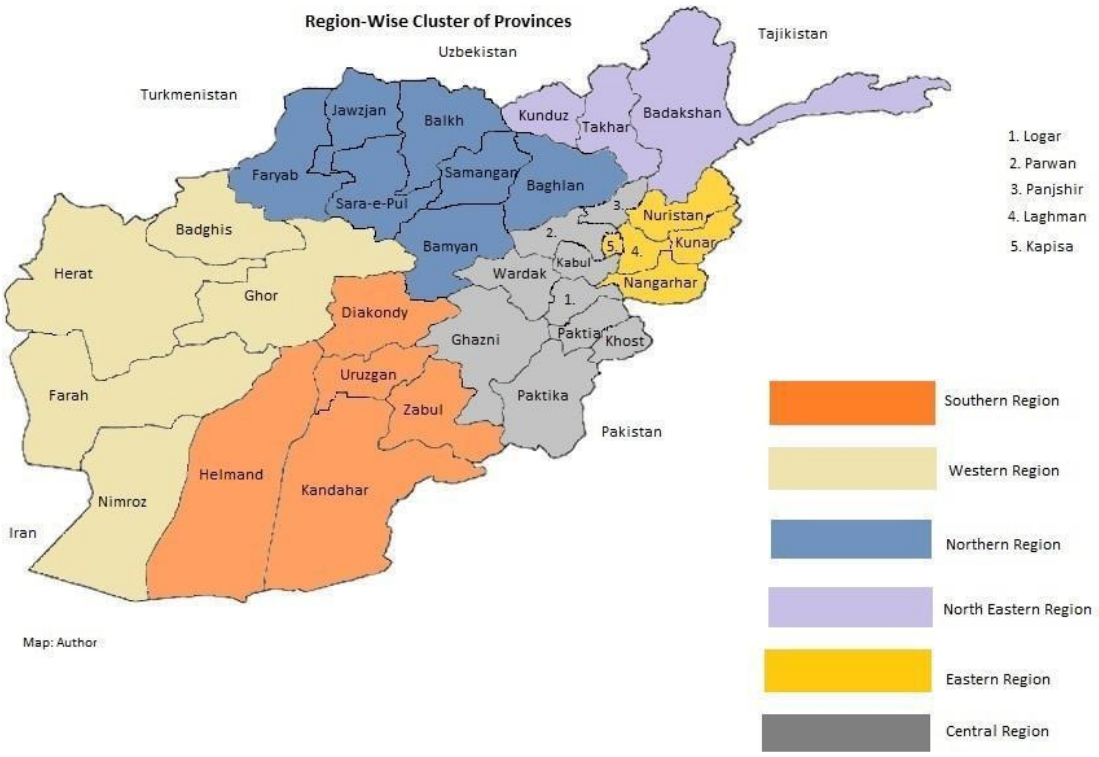

मीडिया में आई ख़बर के अनुसार, जिसमें स्पेशल इंस्पैक्टर जनरल फॉर अफ़ग़ानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन (एसआईजीएआर) के आंकड़ों का हवाला दिया दिया गया था, जुलाई 2017 में तालिबान का 48 प्रशासनिक क्षेत्रों पर या तो कब्जा था या प्रभुत्व था। 2001 में सत्ता से बाहर होने के बाद से अब तक ये उनका सर्वाधिक वर्चस्व क्षेत्र था। महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में तालिबान का प्रभुत्व देश में उनकी बढ़ती ताकत की ओर इशारा कर रहा है। ऊपर से आईएसआईएस की उपस्थिति अफ़ग़ानिस्तान में असुरक्षा की भावना में वृद्धि कर रही है, जिसकी उपस्थिति पूर्व में स्थित प्रांत नांगरहर के अलावा भी देखी जा रही है।

संयुक्त राष्ट्र का अफ़ग़ान मूल्यांकन

राष्ट्रपति बनने से पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प का रुख तत्कालीन राष्ट्रपति ओबामा की अफ़ग़ान नीति के विरुद्ध था। लिहाजा ये कयास लगाए जा रहे थे कि व्हाइट हाउस में नेतृत्व परिवर्तन के पश्चात् अफ़ग़ानिस्तान के प्रति अमेरिकी रणनीति में भी परिवर्तन आएगा। श्री ट्रम्प 2011 से ही अफ़ग़ानिस्तान से सेना वापसी के प्रबल समर्थक थे। राष्ट्रपति पद की अपनी उम्मीदवारी के लिए उन्होंने इसे मुद्दे पर भी अपना रुख स्पष्ट किया। 7 अक्टूबर 2011 को अपने एक ट्वीट में श्री ट्रम्प ने अफ़ग़ानिस्तान में अमेरिकी सेना की उपस्थिति पर सवाल उठाते हुए लिखा था, "हम कब तक अफ़ग़ानिस्तान के पुनर्निर्माण में अपना धन बर्बाद करते रहेंगे? हमें पहले अपने देश का निर्माण करना चाहिए"। हालांकि अफ़ग़ानिस्तान में अमेरिकी लिप्तता पर विचार स्पष्ट रूप से एक नागरिक के तौर पर उनके निजी विचार थे, लेकिन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुनाव प्रचार के दौरान उनका रुख उस वक्त बदला हुआ नज़र आया, जब उन्होंने कहा कि 2001 में अफ़ग़ानिस्तान पर हमला "एक भारी गलती थी," लेकिन वहां की सरकार को बचाने के लिए वहां अमेरिकी सेना का रहना आवश्यक है।

ओबामा की नीति जारी रखते हुए ट्रम्प प्रशासन ने ये भी स्पष्ट कर दिया, कि "अमेरिका का मुख्य उद्देश्य अमेरिका तथा उसके मित्र देशों पर हमला करने के लिए अफ़ग़ानिस्तान को आतंकवादियों का सुरक्षित ठिकाना बनाने से रोकना है।" अपने देश को सुरक्षित रखने की अमेरिकी नीति की अफ़ग़ानिस्तान में अमेरिकी तथा नेटो सेना के कमांडर जॉन डब्ल्यू निकलसन ने भी 9 फरवरी 2017 को वकालत की थी। सिनेट आर्म्ड सर्विसेज़ कमेटी में उन्होंने वक्तव्य दिया, "दुनियाभर में अमेरिका की पहचान के 98 आतंकवादी संगठनों में 20 अफ़ग़ानिस्तान-पाकिस्तान क्षेत्र में उपस्थित हैं।" इस संदर्भ में जनरल निकलसन ने अफ़ग़ानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।

ऐसा लगता है कि ये क्षेत्र दुनियाभर में आतंकवादी गतिविधियों का केन्द्र है। अफ़ग़ानिस्तान में सैनिकों की संख्या कम करने की कोशिश निश्चित रूप से तालिबान तथा आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठनों का मनोबल तथा प्रभाव बढ़ाएगी। इस परिप्रेक्ष्य में ये उम्मीद थी कि ट्रम्प प्रशासन अफ़ग़ानिस्तान से सेना वापस बुलाकर पांव फैलाने के आतंकवादियों के मंसूबे सफल नहीं होने देगा।

ट्रम्प प्रशासन तथा अफ़ग़ानिस्तान नीति

13 जून 2017 को रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस को अफ़ग़ानिस्तान में सैनिकों की संख्या निर्धारित करने का भार सौंपा गया। अप्रैल 2017 में उनके तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एच. आर. मैक मास्टर की जमीनी हालत का जायज़ा लेने के लिए अफ़ग़ानिस्तान यात्रा के पश्चात् ये
निर्णय किया गया। शायद इससे ट्रम्प को अफ़ग़ानिस्तान नीति सुनिश्चित करने में मदद मिली, जो अभी

तक पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों के अनुरूप चली आ रही थी। 15 अगस्त 2017 को मैटिस ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि अफ़ग़ानिस्तान से सेना वापसी समेत सभी विकल्प खुले हुए हैं। ये वक्तव्य अफ़ग़ानिस्तान नीति को लेकर ट्रम्प सरकार की उलझन दर्शाता है। हालांकि हाल में अफ़ग़ानिस्तान पर राष्ट्रपति ट्रम्प की घोषणा स्पष्ट करती है कि वॉशिंगटन अफ़ग़ानिस्तान में अपनी उपस्थिति बनाए रखेगा।

वर्जीनिया में अर्लिंगटन के फोर्ट मायर सैनिक ठिकाने से अपने भाषण में राष्ट्रपति ट्रम्प ने अफ़ग़ानिस्तान की वर्तमान परिस्थितियों का समाधान निकालने में अपने प्रशासन की नीतियां स्पष्ट कीं। अपने भाषण में उन्होंने अफ़ग़ानिस्तान में अमेरिकी सेना की उपस्थिति को सही ठहराते हुए स्वीकार किया कि पद संभालने के पहले वो "मूल रूप से सेना की वापसी" के पक्ष में थे। लेकिन एक राष्ट्रपति की हैसियत से, विशेषकर अफ़ग़ानिस्तान के बारे में निर्णय करना अलग बात है। ट्रम्प ने इराक़ से अमेरिकी सेना की अचानक वापसी को गलत निर्णय बताया, जिसने आईएसआईएस समेत आतंकवादी संगठनों को पनपने का मौका दे दिया। उन्होंने कहा कि इराक़ की गलती अफ़ग़ानिस्तान में भी दोहराने का अर्थ है कि देश में आतंकवादियों को फलने-फूलने का अवसर मिल जाएगा। अफ़ग़ान नीति को दक्षिण एशिया से जोड़ते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका की पहचान के 20 विदेशी आतंकवादी संगठन अफ़ग़ानिस्तान तथा पाकिस्तान में सक्रिय हैं, क्योंकि "पाकिस्तान हमेशा अराजकता, हिंसा तथा आतंक को बढ़ावा देता है"।

राष्ट्रपति ट्रम्प ने अफ़ग़ानिस्तान-पाकिस्तान में आतंकवादी गुटों के हमले रोकने में स्पष्ट रूप से अमेरिकी हितों का हवाला दिया, जो अमेरिका के लिए खतरा हैं। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते आतंकवाद को देखते हुए पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा को लेकर भी चिन्ता जताई और आतंकवादी गुटों के नेटवर्क तथा वित्तीय संसाधन नष्ट करने पर प्रतिबद्धता ज़ाहिर की।

नीति में नया क्या है?

हालांकि नीति की घोषणा में देरी हुई, फिर भी राष्ट्रपति ट्रम्प ने वरिष्ठ सैन्य सलाहकारों के सुझावों के अनुसार अफ़ग़ानिस्तान में अमेरिकी सैन्य भूमिका बढ़ाने पर अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट की। नई नीति तीन मुख्य विन्दुओं पर केन्द्रित है, जो देश तथा क्षेत्र का भविष्य निर्धारित करेंगे। सबसे पहले, सैनिक संख्या में वृद्धि से अफ़ग़ानिस्तान में सैन्य कार्रवाई त्वरित होगी। दूसरा, सेना की मजबूती, तैनाती तथा वापसी से जुड़े निर्णय गोपनीय रखे गए हैं। और तीसरा, पाकिस्तान पर दबाव डालना कि वो अपने क्षेत्र में आतंकवादी गुटों को समर्थन देने की नीति त्याग दे।

इस नीति को कूटनीति, आर्थिक तथा सैनिक कोशिशों का समन्वय बताते हुए राष्ट्रपति ट्रम्प ने तालिबान के साथ राजनीतिक सुलह का विकल्प भी खुला रख छोड़ा है। तालिबान तथा अन्य आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध प्रभावशाली सैनिक कार्रवाई राष्ट्रीय एकता सरकार या नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट (एनयूजी) को भविष्य में जब भी आवश्यकता महसूस हो, शांति स्थापना की कोशिशों को मजबूती प्रदान करेगी। इन

नीति में अगली नई बात है कि सरकार चुनने की ज़िम्मेदारी अफ़ग़ान जनता पर छोड़ दी गई है।

दिलचस्प बात है कि ट्रम्प की अफ़ग़ान नीति में भारत का भी जिक्र है। अफ़ग़ानिस्तान में पुनर्निर्माण तथा पुनर्विकास की प्रक्रिया की सराहना करते हुए ट्रम्प ने इन शब्दों में आर्थिक मदद तथा देश में विकास कार्यों को बढ़ावा देने में भारत से अपनी भूमिका बढ़ाने का आग्रह किया, "हम चाहते हैं कि वो अफ़ग़ानिस्तान के मामले में हमें अधिक मदद दें, विशेषकर आर्थिक सहायता तथा विकास के क्षेत्र में"। इसके अलावा ट्रम्प ने अपनी दक्षिण एशिया नीति के अन्तर्गत ये कहते हुए भारत के साथ सामरिक सहयोग बढ़ाने पर ज़ोर दिया कि, "अमेरिका की दक्षिण एशिया नीति का अन्य महत्त्वपूर्ण भाग है भारत के साथ सामरिक सहयोग विकसित करना - जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका का महत्त्पूर्ण सामरिक तथा आर्थिक सहयोगी है"।

शर्तों पर आधारित वापसी

अफ़ग़ानिस्तान के लिए पुरानी अमेरिकी नीति से एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन था, कि वापसी के लिए समय-सीमा निर्धारित करने के बजाय शर्तों पर वापसी सुनिश्चित की जाए। निश्चित समय के पश्चात् वापसी की नीति का पालन 2001 से किया जा रहा था। अफ़ग़ानिस्तान में अमेरिकी सेना का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि उनकी नीति का मुख्य लक्ष्य दुश्मनों से लड़ना और जीतना है। उन्होंने कहा कि, "अब से जीत की एक स्पष्ट परिभाषा होगी: अपने दुश्मनों पर हमला करना, आईएसआईएस का नामोनिशान मिटाना, अल क़ायदा को कुचलना, तालिबान को अफ़ग़ानिस्तान पर कब्जा करने से रोकना तथा अमेरिका के विरुद्ध सामूहिक आतंकवादी हमलों को उत्पन्न होने से पहले ही समाप्त कर देना"। नए प्रशासन का मानना है कि समय पर आधारित वापसी की पुरानी नीति अफ़ग़ानिस्तान में अमेरिका तथा उसके सहयोगियों के लिए हानिकारक थी, क्योंकि इससे शत्रु सेनाओं को अफ़ग़ान, अमेरिकी तथा सहयोगी सेनाओं को निशाना बनाने के लिए पूर्व नियोजित तैयारियां करने का अवसर मिल जाता था। इसके बदले सेना की वापसी तथा अन्य प्रायोगिक तकनीकियों के लिए जमीनी सच्चाईयों को मानक सिद्धांत बनाना चाहिए।

पाकिस्तान की भूमिका

राष्ट्रपति ट्रम्प की नई अफ़ग़ान नीति के महत्त्वपूर्ण पहलुओं में पाकिस्तान के प्रति उसका दृष्टिकोण भी एक है। 'रणनीतिक गहराई' के अन्तर्गत इस्लामाबाद का आतंकवादी तत्वों को अपनी जमीन पर समर्थन की नीति को महसूस करते हुए राष्ट्रपति ट्रम्प ने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया कि वो "सभ्यता, नियमन तथा शांति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करे" एवं "अमेरिकी सेवा के सदस्यों तथा अधिकारियों को निशाना बनानेवाले आतंकवादियों तथा उग्रपंथियों को शरण देना बंद करे"। इस सन्दर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति, पाकिस्तान की उस दोहरी नीति के आलोचक थे, जिसमें एक ओर वो अमेरिका से भारी-भरकम वित्तीय सहायता प्राप्त करता था तथा दूसरी ओर अफ़ग़ानिस्तान में अमेरिकी सेना से लड़नेवाले आतंकवादी

संगठनों को शरण देता था। इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रम्प ने पाकिस्तान से कहा कि वो अपनी नीति में परिवर्तन लाए तथा क्षेत्र में शांति एवं स्थायित्व बनाने में योगदान दे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि "हम पाकिस्तान को आतंकवादियों, तालिबान तथा अन्य वैसे संगठनों का सुरक्षित शरणगाह बनते देखकर चुप नहीं बैठ सकते, जो इस क्षेत्र तथा अन्य स्थानों के लिए भी खतरा हैं"। पाकिस्तान को ये भी चेतावनी दी गई है कि अगर अमेरिकी सेवा के सदस्यों को निशाना बनानेवाले किसी चरमपंथी या आतंकवादी को शरण दी गई तो उसके साथ कोई साझेदारी जारी नहीं रखी जा सकती।

तालिबान को संदेश

अफ़ग़ानिस्तान में सुरक्षा स्थिति बदतर होने का कारण तालिबान का फिर से सिर उठाना है। अफ़ग़ानिस्तान में स्थित आतंकी संगठनों को सख्त चेतावनी के रूप में नई रणनीति में शत्रु सेना से लड़ने की बात कही गई है, जिसमें तालिबान भी शामिल है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा, "...वॉशिंगटन डी.सी. में बैठकर सूक्ष्म प्रबंधन युद्ध नहीं जीता जा सकता," लिहाजा नए प्रशासन ने युद्धभूमि में सैनिकों पर लगनेवाले परिचालन सम्बंधी प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया है, जो अफ़ग़ानिस्तान में चरमपंथी संगठनों के साथ लड़ रहे हैं। मोसुल (इराक़) के अनुभव से ये कदम उठाया गया है, जहां परिचालन प्रतिबंध हटाने के सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। भविष्य में तालिबान के साथ राजनीतिक सुलह का विकल्प भी खुला रखा गया है। नई रणनीति में आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई मजबूत करना शामिल है, जिनमें तालिबान भी शामिल है। ट्रम्प की टिप्पणियां अमेरिकी सैन्य अभियान के उद्देश्य को दर्शाती हैं, जो आईएसआईएस, अल क़ायदा, तालिबान तथा अन्य संगठनों पर जीत हासिल करना है।

नीति पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया

अफ़ग़ानिस्तान तथा दक्षिण एशिया के लिए ट्रम्प की नीति पर क्षेत्र तथा अन्य स्थानों में अपेक्षित प्रतिक्रिया हुई। कुछ ने इसे सकारात्मक कदम के रूप में देखा, जबकि दूसरों ने इसकी आलोचना की। उदाहरण के लिए रूस तथा चीन ने नई नीति की प्रभावशीलता पर संदेह व्यक्त किया। पाकिस्तान ने नई नीति का विरोध किया, जबकि युनाइटेड किंगडम, जर्मनी, भारत तथा अफ़ग़ानिस्तान ने नीति का समर्थन किया।

रूस: मॉस्को ने राष्ट्रपति ट्रम्प की नई रणनीति को राष्ट्रपति ओबामा की नीति के समान बताया, जो क्षेत्र की स्थिति सुधारने में नाकाम रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा, "अफसोस की बात है कि नई रणनीति में आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के अफ़ग़ानिस्तान में प्रभाव फैलाने के खतरे से निपटने का कोई उल्लेख नहीं है, जो तेजी से अफ़ग़ानिस्तान में अपने पांव पसारचे जा रहे हैं, साथ ही अफ़ग़ानिस्तान में नशीले पदार्थों का उत्पादन पर रोक भी पूरी तरह अनदेखा कर दिया गया है"। अपने वक्तव्य में उन्होंने उम्मीद जताई कि अफ़ग़ानिस्तान में अमेरिका सैनिकों की वृद्धि उस देश की संप्रभुता तथा राष्ट्रीय हितों का उल्लंघन नहीं करेगी।

चीन: इस रणनीति से अफ़ग़ानिस्तान तथा दक्षिण एशिया में सुरक्षा तथा स्थायित्व को प्रोत्साहन मिलेगा, इस उम्मीद के साथ चीन, पाकिस्तान के समर्थन में आगे आया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चूनिंग ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में आगे रहा है तथा उसने "महान बलिदान" दिये हैं एवं युद्ध में "महत्त्वपूर्ण योगदान" दिया है। "हमारा मानना है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद के विरुद्ध पाकिस्तान के प्रयासों को पूरी मान्यता देनी चाहिए"।

पाकिस्तान: अमेरिका की अफ़ग़ानिस्तान तथा दक्षिण एशिया की नीति पर पाकिस्तान ने सख्त विरोध प्रकट किया है। राष्ट्रपति ट्रम्प की नई रणनीति की घोषणा के बाद 22 अगस्त 2017 को प्रधानमंत्री शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अफ़ग़ानिस्तान तथा दक्षिण एशिया के लिए ट्रम्प की रणनीति पर विचार-विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री को 24 अगस्त 2017 को होनेवाली राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (एनएससी) की बैठक में मुद्दा उठाने का अधिकार दिया गया। अपनी बैठक में एनएससी ने नई रणनीति पर राष्ट्रपति ट्रम्प के वक्तव्य को खारिज कर दिया तथा नई अमेरिकी नीति पर पाकिस्तान के रुख पर सभी मित्र देशों तथा सहयोगियों को एकमत करने का निश्चय किया।

अमेरिका की अफ़ग़ान नीति पर निराशा व्यक्त करते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने 22 अगस्त 2017 को डोनाल्ड ट्रम्प के उन आरोपों का खारिज कर दिया, जिसमें पाकिस्तान को "अराजकता तत्वों" का सुरक्षित आश्रय बताया गया था। अपने जवाब में उसने कहा, "अपनी नीति के अनुसार पाकिस्तान अपनी जमीन का प्रयोग किसी देश के विरुद्ध नहीं करने देता है। सुरक्षित आश्रय होने का झूठा आरोप लगाने के बजाय़ अमेरिका को पाकिस्तान के साथ मिलकर आतंकवाद उन्मूलन के लिए काम करना चाहिए।"

विदेश मंत्रालय के बयान में ये भी कहा गया, "दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान से अधिक आतंकवाद से प्रभावित नहीं रहा है, जो अक्सर हमारी सीमाओं के बाहर से पनपते हैं। लिहाजा ये निराशाजनक है कि अमेरिकी रणनीतिक वक्तव्य में पाकिस्तान राष्ट्र के विशाल बलिदानों की उपेक्षा की गई है।"

विरोध स्वरूप विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन से मुलाकात के लिए वॉशिंगटन की अपनी पूर्व निर्धारित यात्रा में विलम्ब किया तथा पहले चीन, रूस एवं तुर्की की यात्रा की, जो संभवत: अमेरिकी आरोपों के विरुद्ध कूटनीतिक लामबंदी के सिनेट के निर्णय के अनुरूप था। दूसरी ओर निचले सदन ने एकमत से प्रस्ताव पारित कर सरकार से पड़ोसी अफ़ग़ानिस्तान में अमेरिका के नेतृत्व वाले नेटो को सप्लाई लाइन स्थगित करने पर विचार करने की अपील की।

युनाइटेड किंगडम: युनाइटेड किंगडम ने अफ़ग़ानिस्तान में सैनिक अभियान बढ़ाने के राष्ट्रपति ट्रम्प की प्रतिबद्धता का स्वागत किया। "अमेरिकी प्रतिबद्धता का स्वागत है," ब्रिटिश रक्षा मंत्री माइकल फैलन ने

एक वक्तव्य में कहा। "ये हमारे हित में है कि अफ़ग़ानिस्तान अधिक सम्पन्न तथा सुरक्षित बने। इसी कारण जून में हमने अपनी सैनिकों की संख्या में वृद्धि की घोषणा की थी।"

जर्मनी: नेटो के नेतृत्व वाले समर्थक मिशन के रूप में अफ़ग़ानिस्तान में जर्मनी के लगभग 98032 सैनिक हैं तथा उसने राष्ट्रपति ट्रम्प की नई अफ़ग़ान नीति की प्रशंसा की है। हालांकि वो अधिक योगदान देनेवाले प्रारम्भिक देशों में शामिल नहीं होगा। जर्मन रक्षा मंत्री उर्सुला वॉन डेर लियन ने अपने ट्वीट में कहा कि "हमने पिछले साल अपनै सैनिकों की संख्या में 18% की वृद्धि की है, जबकि उस समय अन्य देश अपनी सेनाओं में कटौती कर रहे थे। लिहाजा हम खुद को उन देशों में नहीं पाते, जिनसे अधिक सैनिक सहयोग के लिए कहा जाए।"

भारत: भारत युद्धग्रस्त अफ़ग़ानिस्तान के पुनर्निर्माण में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। उसने सरकार तथा अफ़ग़ानिस्तान की जनता को समर्थन देने एवं उस देश में शांति, सुरक्षा, स्थायित्व व समृद्धि लाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। भारत ने चुनौतियों का सामना कर रहे अफ़ग़ानिस्तान में आतंकवादियों के सुरक्षित आश्रय तथा सीमा पार से अन्य रूपों में मदद पर लगाम कसने के ट्रम्प के संकल्प का समर्थन किया।

अफ़ग़ानिस्तान: राष्ट्रीय एकता सरकार (एनयूज़ी) के दोनों नेताओं ने नई नीति का स्वागत किया। राष्ट्रपति अशरफ़ घनी ने कहा, "मैं आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के प्रयासों तथा आतंकवाद के खतरों से लड़ने की संयुक्त कोशिशों के लिए राष्ट्रपति ट्रम्प तथा अफ़ग़ानिस्तान की जनता का आभारी हूं।" मुख्य कार्यकारी अधिकारी अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने नई रणनीति का स्वागत करते हुए कहा कि अफ़ग़ानिस्तान तथा यहां की जनता के प्रति अमेरिका की नई प्रतिबद्धता आतंकवादियों से निपटने तथा देश में शांति स्थापित करने की दिशा में एक नया अवसर है।

नेटो: नेटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने अफ़ग़ानिस्तान तथा उस क्षेत्र के प्रति राष्ट्रपति ट्रम्प की स्थितियों पर आधारित दृष्टिकोण का स्वागत किया। क्षेत्र में आतंकवादियों के लिए सुरक्षित आश्रय के विषय में ट्रम्प के विचारों का स्वागत करते हुए महासचिव स्टोल्टेनबर्ग ने कहा, "हम क्षेत्र के सभी देशों से आग्रह करते हैं कि वो आतंकवादियों को पनाह देना बंद करें, शांति तथा पुनर्निर्माण का समर्थन करें एवं एक स्थाई तथा सुरक्षित अफ़ग़ानिस्तान बनाने में योगदान दें।" स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि "पिछले कुछ हफ्तों में 15 से अधिक राष्ट्रों ने मिशन को समर्थन देने के लिए अतिरिक्त सहयोग देने का वादा किया है।"

मूल्यांकन

यद्यपि अफ़ग़ान नीति ने आतंकवादी गुटों का सामना कर रहे अफ़ग़ान तथा सहयोगी ताकतों में आशा की भावना का संचार किया है, इस क्षेत्र के अन्य देशों को भी आगे आना चाहिए, जो सैनिक कार्रवाई के साथ

समस्या का राजनीतिक समाधान प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं। इस नीति से उन आतंकवादियों तथा उग्रवादी गुटों के विरुद्ध युद्ध में नया जोश पैदा होने की उम्मीद है, जो देश में सक्रिय हैं। ये देखना बाकी है कि कुछेक हजार नए सैनिकों को जोड़कर तालिबान को उभरने से, तथा आईएसआईएस एवं अन्य आतंकवादी गुटों के विस्तार से कैसे रोका जा सकता है, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने तथा आतंकवादी नेटवर्क को समाप्त करने में अब तक एक लाख से अधिक विदेशी सैनिक नाकाम रहे हैं। सबसे महत्त्वपूर्ण बात है कि अफ़ग़ानिस्तान समस्या का दीर्घकालीन समाधान प्राप्त करने में पाकिस्तान का सहयोग अनिवार्य है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा उठाए दो मुख्य सवाल अनुत्तरित हैं;

- अगर पाकिस्तान राष्ट्रपति ट्रम्प की नीतियों पर अमल नहीं करता, तो अमेरिका के पास क्या विकल्प होगा?

- अगर पाकिस्तान अफ़ग़ानिस्तान में अमेरिका, नेटो तथा उनके सहयोगियों की सेना के लिए संचार के महत्त्वपूर्ण साधन रोक देता है, तो उनके पास क्या विकल्प है?

राष्ट्रपति ट्रम्प की नीति ने पाकिस्तान के प्रति अमेरिका के वर्तमान आधिकारिक रुख को दुरुस्त करने का प्रयास किया है, एक ऐसा देश जो लम्बे समय से अमेरिका से वित्तीय लाभ उठाता रहा है, साथ ही क्षेत्र में अमेरिकी हितों की लगातार अनदेखी करता रहा है। अमेरिका ने महसूस किया है कि पाकिस्तान समस्या का हिस्सा भी है तथा समाधान भी, क्योंकि तालिबान तथा हक्कानी नेटवर्क उसी देश में स्थित हैं। 'आतंक के विरुद्ध युद्ध' में इस्लामाबाद की दोहरी नीति को वॉशिंगटन ऐसे समय में अनदेखा नहीं कर सकता, जब अफ़ग़ानिस्तान में आतंकवादी हमलों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि ये देखना बाकी है कि क्या पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को आश्रय देना तथा पड़ोसी देशों में अपने छद्म युद्ध को बढ़ावा देना बंद करता है अथवा नहीं।

बाहरी खतरों के अलावा अफ़ग़ानिस्तान लगातार अंदरूनी खतरे की आशंका से प्रभावित है, जिसका नाम तालिबान है। ट्रम्प की नीतियों पर प्रतिक्रिया देते हुए तथा नए क्षेत्रों पर कब्जा करने में अपनी संभावित परेशानियों को महसूस करते हुए तालिबान ने नई नीति को "अमेरिकी सैनिकों की ज़िंदगी बर्बाद" करनेवाला बताया। तालिबान ने राष्ट्रपति ट्रम्प की नीति को अस्पष्ट बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि "इसमें कुछ भी नया नहीं है।" साथ ही चेतावनी दी कि "अफ़ग़ानिस्तान, अमेरिका के लिए कब्रगाह बन जाएगा।"

यद्यपि दक्षिण एशिया तथा विस्तृत भारत-प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा के अमेरिका के साझा उद्देश्यों के लिए प्रतिबद्धता है, लेकिन ट्रम्प के भाषण में रूस, चीन, ईरान तथा मध्य एशियाई देशों जैसे अन्य क्षेत्रीय साझेदारों का कोई उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति ट्रम्प की स्थिति पर आधारित सैन्य वापसी अफ़ग़ानिस्तान में स्थिति से जूझने के लिए नई आशा पैदा करती है, लेकिन 'आतंक के विरुद्ध युद्ध' में घरेलू तथा बाहरी जैसे दोहरे खतरे गंभीर चुनौतियां पैदा करते हैं।

****

*डॉ. निहार रंजन दास, शोध अध्येता, विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली।

डिस्क्लेमरः उपरोक्त विचार शोध अध्येता के हैं तथा परिषद के विचारों को प्रतिबिम्बित नहीं करते।

संलग्नक - I

अगस्त 21, 2017

अफ़ग़ानिस्तान तथा दक्षिण एशिया में रणनीति पर राष्ट्रपति ट्रम्प की टिप्पणियां

फोर्ट मायर्स

अर्लिंग्टन, वर्जीनिया

9:02 पी. एम. ईडीटी

राष्ट्रपतिः बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कृपया बैठ जाएं।

उपराष्ट्रपति पेंस, विदेश मंत्री टिल्लरसन, कैबिनेट के सदस्य, जनरल डन्फोर्ड, उप मंत्री शानाहम तथा कर्नल दुग्गन। फोर्ट मायर्स में उपस्थित पुरुषों तथा महिलाओं एवं देश तथा विदेश में अमेरिकी सेना के सभी सदस्यों को धन्यवाद।
हम समुद्र में एक दुखद टक्कर में घायल होनेवाले तथा अपनी जान खोनेवाले बहादुर सैनिकों, तथा उनकी तलाश व राहत कार्य करनेवालों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं तथा प्रार्थना समर्पित करते हैं।

मैं यहां आज रात अफ़ग़ानिस्तान तथा दक्षिणी एशिया के प्रति अपनी नीतियां स्पष्ट कर रहा हूं। लेकिन अपनी नई रणनीति स्पष्ट करने से पहले मैं यहां आज रात अपने साथ उपस्थित सर्विसमेन, अपने ठिकानों से हमें देखनेवालों तथा घर में बैठकर मुझे सुननेवाले, सभी अमेरिकियों से कुछ कहना चाहूंगा।

गणराज्य की स्थापना के बाद से हमारे देश ने विशेष दर्जे के नायक पैदा किये हैं, जिनकी निस्वार्थ सेवा, साहस तथा समाधान की क्षमता मानव इतिहास में बेजोड़ है।

हर पीढ़ी के अमेरिकी देशभक्तों ने अपने देश तथा हमारी स्वतंत्रता के लिए युद्धभूमि में अंतिम सांस तक

प्रयत्न किये हैं। हालांकि उनकी ज़िंदगी छोटी थी, लेकिन अपने कर्मों के कारण वो अमर हो गए।

हमारे गणराज्य को सुरक्षित रखने के लिए बलिदान देनेवालों से हमें अपने देश की एकता तथा मजबूती बनाए रखने एवं ईश्वर की कृपा से एक देश बने रहने की प्रेरणा मिलती है। हमारी सेना के पुरुष तथा महिलाएं एक टीम के रूप में कार्य करते हैं, जिनका लक्ष्य एक होता है तथा जो अपने उद्देश्य की भावनाएं साझा करते हैं।

वो हर जाति, जातीयता, पंथ तथा रंग से ऊपर उठकर एक साथ मिलकर सेवा करते हैं तथा बिलकुल सामंजस्य के साथ एक साथ अपना बलिदान देते हैं। यही कारण है कि सभी सर्विसमेन भाई-बहन हैं। वो एक ही परिवार का हिस्सा हैं, जिसे हम अमेरिकी परिवार कहते हैं। उनका शपथ एक होता है, एक झंडे के तले लड़ते हैं तथा एक कानून के अन्तर्गत जीवन निर्वाह करते हैं। वो देश तथा एक-दूसरे के लिए समान उद्देश्य, आपसी विश्वास तथा निस्वार्थ भावनाओं में बंधे होते हैं।

एक सैनिक समझता है कि एक राष्ट्र के रूप में हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे समुदाय के किसी सदस्य पर घाव उत्पन्न करने का अर्थ सभी को चोट पहुंचाना होता है। जब अमेरिका के किसी एक भाग को चोट पहुंचती है, तो हम सभी को दर्द होता है। अगर एक व्यक्ति के साथ अन्याय होता है, तो हम सभी एक साथ पीड़ित होते हैं।

हमारे देश के प्रति वफादारी एक-दूसरे के प्रति निष्ठा की मांग करती है। अमेरिका के प्रति प्रेम का अर्थ है सभी अमेरिकियों के प्रति प्रेम। जब कोई देशभक्ति की राह पर चलता है तो उसमें भेदभाव, कट्टरता तथा नफरत के लिए जगह नहीं होती।

जब हम विदेशी धरती पर युद्ध के लिए पुरुषों और महिलाओं को भेजते हैं तो उनका हक बनता है कि वापस लौटने पर वो अपने देश के भीतर युद्ध की स्थिति न देखें। हम दुनिया में शांति वाहक तब तक नहीं बन सकते, जब तक हम एक-दूसरे के साथ शांति से नहीं रहते।

हम विदेश में अपने दुश्मनों को पराजित करने के लिए अपने सबसे बुद्धिमान आदमी भेजते हैं -- और हमेशा जीत ते हैं - हमें अपने अंदरूनी विभाजन को भी भरने का साहस उत्पन्न करना चाहिए। आईये, हम देश के लिए लड़नेवाले पुरुषों तथा महिलाओं से एक सरल वादा करें, कि जब वो रणभूमि से अपने घर वापस लौटें, तो एक ऐसे देश का दीदार करें, जिसने प्रेम तथा भरोसे के पवित्र बंधन को एकता के सूत्र में बांधने के लिए पुनर्जाग्रत किया है।

अमेरिकी सेना और दुनियाभर में हमारे बहुत से मित्रों की सतर्कता तथा कौशल को धन्यवाद, 11 सितम्बर की भयावहता हमें याद है - उसे कभी कोई नहीं भूल सकता - ऐसा कभी नहीं होना चाहिए।

फिर हमें उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, जिसके बारे में बात करने के लिए आज रात मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। 11 सितम्बर के आतंकवादी हमलों के लगभग 16 वर्षों बाद भी, भारी संख्या में रक्तपात, बलिदान तथा काफी पैसा खर्च होने के बाद भी, अमेरिकी जनता बिना विजय हासिल किये सतत लड़ रही है। अफ़ग़ानिस्तान में चल रहे युद्ध से ये बिलकुल स्पष्ट है, अमेरिका के इतिहास में चलनेवाला सबसे लम्बा युद्ध - 17 वर्ष।

अमेरिकी जनता की हताशा मैं भी साझा करता हूं। मैं एक ऐसी विदेश नीति को लेकर उनकी हताशा साझा करता हूं, जिसमें अपने मनमुताबिक देशों के पुनर्निर्माण में लम्बा वक्त, धन तथा सबसे महत्त्वपूर्ण ज़िंदगियों की आहूति दी गई, बजाय सभी अन्य मुद्दों से ऊपर अपनी स्वयं की सुरक्षा को महत्त्व देने के।

यही कारण है कि सत्ता में आने के तुरंत बाद मैंने रक्षा मंत्री मैटिस तथा अपने राष्ट्रीय सुरक्षा टीम को अफ़ग़ानिस्तान तथा दक्षिण एशिया में सभी रणनीतिक विकल्पों की व्यापक समीक्षा करने को कहा।

मेरी मूल प्रवृत्ति सामने लाने की रहा है - आदतन मैं अपनी प्रवृत्तियों का ही पालन करता हूं। पूरी ज़िंदगी मैं सुनता रहा कि जब आप ओवल दफ्तर में बैठते हैं, या दूसरे शब्दों में जब आप अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाते हैं तो निर्णय बदल जाते हैं। लिहाजा मैंने अफ़ग़ानिस्तान के बारे में विस्तार से तथा सभी संभावित कोण से अध्ययन किया। कई बैठकों के बाद कैबिनेट के सदस्यों तथा जनरलों के साथ रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए पिछले शुक्रवार को कैम्प डेविड में आखिरी बैठक हुई। अफ़ग़ानिस्तान में अमेरिका के मुख्य हितों के संदर्भ में मैं तीन परिणामों तक पहुंचा हूं।

सर्वप्रथम भारी बलिदानों तथा विशेषकर ज़िंदगियों के बलिदानों के बाद हमारे देश को सम्मानजनक तथा स्थाई परिणाम प्राप्त होने चाहिए। युद्ध में देश का प्रतिनिधित्व करनेवाले पुरुषों तथा महिलाओं के पास विजय प्राप्त करने की योजना होनी चाहिए। उन्हें लड़ने तथा जीतने के लिए आवश्यकता के अनुरूप उपकरण एवं विश्वास अर्जित होने चाहिए।

दूसरा, जल्दबाजी में वापसी ना तो पूर्वानुमानित है और न स्वीकार्य। 9/11, हमारे इतिहास के सबसे ज़ोरदार आतंकवादी हमला की योजना तथा निर्देशन अफ़ग़ानिस्तान से हुआ था, क्योंकि उस देश में एक ऐसी सरकार थी जो आतंकवादियों को सुरक्षा तथा पनाह देती थी। जल्दबाजी में वापसी से एक शून्य पैदा होगा, जिसे आईएसआईएस तथा अल क़ायदा समेत आतंकवादी संगठन तुरंत भरेंगे, जैसे 11 सितम्बर से पहले हुआ था।

और जैसा कि हम जानते हैं, 2011 में अमेरिका ने जल्दबाजी तथा गलतफहमी में इराक से वापसी की। नतीजतन हमारी कड़ी मेहनत से प्राप्त परिणाम वापस आतंकवादियों के हाथ लग गए। हमारे सैनिकों ने जिन शहरों के लिए युद्ध किया, जिनकी स्वतंत्रता के लिए अपना खून बहाया, उनकी आंखों के सामने

आईएसआईएस नामक आतंकवादी संगठन ने उनपर कब्जा कर लिया। जल्दबाजी में वापसी के कारण उत्पन्न शून्य ने आईएसआईएस को उसे भरने, स्वयं को मजबूत बनाने, नई भर्तियां करने तथा आक्रमण करने का अवसर दे दिया। हमारे नेताओं ने इराक़ में जो गलतियां कीं, उन्हें हम अफ़ग़ानिस्तान में नहीं दोहरा सकते।

तीसरा और अंतिम, मैंने निष्कर्ष निकाला है कि अफ़ग़ानिस्तान में सीमावर्ती क्षेत्रों से हम भारी सुरक्षा खतरों का सामना कर रहे हैं। आज अमेरिका के संज्ञान में आए 20 आतंकवादी संगठन अफ़ग़ानिस्तान तथा पाकिस्तान में सक्रिय हैं - जो दुनिया के किसी भी क्षेत्र की तुलना में आतंकवादियों का सर्वाधिक जमावड़ा है।

पाकिस्तान हमेशा से अराजकता, हिंसा तथा आतंक फैलानेवालों के लिए स्वर्ग रहा है। अत्यधिक खतरा ये है कि पाकिस्तान तथा भारत दोनों परमाणु हथियारों से लैस देश हैं, जिनके बीच आपसी तनाव युद्ध का कारण बन सकता है। और ऐसा होने की काफी आशंका है।

इस सच्चाई से किसी को इंकार नहीं कि हमें अफ़ग़ानिस्तान तथा दक्षिणी एशिया में एक चुनौतीपूर्ण तथा परेशानी भरी स्थिति विरासत में मिली है। लेकिन हमारे पास समय पर वापसी कर स्थिति को सामान्य बनाने अथवा बेहतर निर्णय करने की स्वतंत्रता नहीं है। जब मैं राष्ट्रपति बना, तो मुझे बेहद बुरी तथा जटिल विरासत मिली, लेकिन मुझे पूरा अहसास था, कि ये विशाल तथा पेचीदगी भरी समस्याएं हैं। लेकिन किसी ना किसी तरह इन समस्याओं का समाधान होगा - मैं समस्याओं का समाधान करने में माहिर हूं -- और अंत में विजय हमारी ही होगी।

हमें उन तमाम दुनियावी चुनौतियों की वास्तविकता का सामना करना चाहिए, जिन खतरों का हम सामना कर रहे हैं, जो आज हमारी सारी समस्याओं की जड़ हैं तथा जो जल्दबाजी में वापसी के बुरे परिणामों का पूर्वानुमान हैं।

हमें बार्सिलोना में पिछले हफ्ते हुए नीच, शातिर हमले से ध्यानपूर्वक सीख लेने की आवश्यकता है, ताकि हम ये समझ सकें कि आतंकवादी संगठन निर्दोष पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की सामूहिक हत्या करने से पीछे नहीं हटेंगे। आपने स्वयं इसे देखा है। भयानक।

जैसा तीन महीने पहले मैंने सऊदी अरब में अपने भाषण में उल्लेख किया था, अमेरिका तथा हमारे सहयोगी उनके क्षेत्र से आतंकवादियों के खात्मे, उनकी आर्थिक मदद रोकने तथा उनकी शैतानी विचारधारा का झूठ उजागर करने के लिए कटिबद्ध हैं।

निर्दोष लोगों की हत्या करनेवाले आतंकवादियों को इस जीवन में या अगले जीवन में कोई पुण्य प्राप्त नहीं

होगा। वो और कुछ नहीं, सिर्फ ठग, अपराधी और शिकारी हैं और - यही सही है - वो पराजित होंगे। अपने सहयोगियों के साथ मिलकर हम उनका आत्मविश्वास तोड़ेंगे, उनकी भर्तियां बंद करेंगे, अपनी सीमाओं से उन्हें दूर रखेंगे, और हां, हम उन्हें पराजित करेंगे, बुरी तरह पराजित करेंगे।

अफ़ग़ानिस्तान तथा पाकिस्तान में अमेरिकी हित स्पष्ट हैं। हमें आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों को समाप्त करना होगा, जो अमेरिकी सुरक्षा पर खतरा हैं। साथ ही हमें परमाणु हथियारों तथा सामग्रियों को आतंकवादियों के हाथों पड़ने तथा हमारे विरुद्ध प्रयोग करने से, अथवा दुनिया में कहीं भी प्रयोग करने से रोकना होगा।

लेकिन इस युद्ध को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम इतिहास से भी सबक सीखेंगे। हमारी व्यापक समीक्षा के परिणामस्वरूप अफ़ग़ानिस्तान तथा दक्षिण एशिया में अमेरिकी रणनीति में निम्नलिखित तरीकों से भारी परिवर्तन होगा:

हमारी नई रणनीति का एक मुख्य स्तम्भ समय पर आधारित वापसी की बजाय वापसी का आधार स्थितियों का आकलन होगा। मैं कई बार बता चुका हूं कि आरम्भ में ही सैनिक कार्रवाई की समाप्ति तथा सेना की वापसी की तारीखों की घोषणा करना किस प्रकार अमेरिका के लिए हानिकारक है। भविष्य की सैनिक गतिविधियों के लिए हम सैनिकों की संख्या अथवा अपनी आगामी योजनाओं के संदर्भ में कोई बात नहीं करेंगे।

अब से कोई मनमुताबिक समय सारणी नहीं, बल्कि सिर्फ जमीनी स्थितियां ही हमारी भविष्य की रणनीति होंगी। अमेरिका के दुश्मनों को हमारी योजना अथवा हमारी वापसी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मैं ये बताने नहीं जा रहा, कि हम कब हमला करेंगे, लेकिन ये सुनिश्चित है कि हम हमला अवश्य करेंगे।

हमारी नई रणनीति का एक और मौलिक स्तम्भ अमेरिकी ताकत के सभी अवयवों - कूटनीतिक, आर्थिक तथा सेना को एकीकृत करना है - ताकि सफल परिणाम प्राप्त हों।

प्रभावशाली सैनिक कार्रवाई के बाद एक दिन शायद अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान के तत्वों को शामिल कर राजनीतिक समाधान खोजना संभव हो सकता है। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि ऐसा कब होगा। अमेरिका, अफ़ग़ान सरकार तथा अफ़ग़ान सेना को अपना समर्थन जारी रखेगा, क्योंकि वो तालिबान का सामना कर रहे हैं।

अंतत: अपना भविष्य अपने हाथों में लेना, अपने समाज पर शासन करना, तथा हमेशा के लिए शांति स्थापित करना अफ़ग़ानिस्तान की जनता पर निर्भर करता है। हम एक सहयोगी तथा एक मित्र हैं, लेकिन हम अफ़ग़ान की जनता को जीना नहीं सिखाएंगे या अपने जटिल समाज के प्रशासन के लिए निर्देशित नहीं

करेंगे। हम फिर से राष्ट्र निर्माण नहीं कर रहे। हम आतंकवादियों को समाप्त कर रहे हैं।

हमारी रणनीति का अगला स्तम्भ पाकिस्तान के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन तथा उससे कैसे निपटा जाए, ये सुनिश्चित करना है। हम पाकिस्तान को आतंकवादी संगठनों, तालिबान तथा क्षेत्र में तथा अन्य जगहों पर खतरा उत्पन्न करनेवाले अन्य संगठनों का सुरक्षित आश्रय बनते हुए चुपचाप बैठकर नहीं देख सकते। अफ़ग़ानिस्तान में हमारे साथ सहयोग कर पाकिस्तान को काफी लाभान्वित होना है। अपराधियों तथा आतंकवादियों को आश्रय देकर उसे काफी कुछ खोना है।

अतीत में पाकिस्तान हमारा महत्त्वपूर्ण सहयोगी रहा है। हमारी सेनाओं ने साझा दुश्मनों के विरुद्ध साथ मिलकर कार्रवाई की है। पाकिस्तानी जनता को आतंकवाद तथा उग्रवाद से काफी नुकसान पहुंचा है। हम उन योगदानों तथा बलिदानों को समझते हैं।

लेकिन पाकिस्तान ने उन संगठनों को भी आश्रय दिया है, जो प्रतिदिन हमारे लोगों को मारने का प्रयास करते हैं। हम पाकिस्तान को अरबों डॉलर दे रहे हैं और वो उन्हीं आतंकवादियों को आश्रय दे रहा है, जिनसे हम लड़ रहे हैं। लेकिन इसे बदलना होगा, और तुरंत बदलना होगा। आतंकवादियों तथा उग्रवादियों को आश्रय देनेवाले वैसे किसी देश के साथ साझेदारी नहीं की जा सकती, जो अमेरिकी सेवा के सदस्यों तथा अधिकारियों को निशाना बना रहे हों। पाकिस्तान के लिए वक्त आ गया है कि वो सभ्यता, नियम तथा शांति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाए।

दक्षिण एशिया में अमेरिकी रणनीति का एक और महत्त्वपूर्ण अंग भारत के साथ अपनी रणनीतिक भागीदारी को अधिक विकसित करना है - जो दुनिया का सबसे विशाल लोकतंत्र तथा अमेरिका का महत्त्वपूर्ण सामरिक तथा आर्थिक सहयोगी है। हम अफ़ग़ानिस्तान में स्थायित्व लाने की भारत की कोशिशों की सराहना करते हैं, लेकिन भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार में अरबों डॉलर की आमदनी की है, और हम चाहते हैं कि वो अफ़ग़ानिस्तान में हमारे साथ, विशेषकर आर्थिक मदद तथा विकास के क्षेत्र में अधिक सहयोग करे। हम दक्षिण एशिया तथा भारत-प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा के साझा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध हैं।

अंत में मेरा प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि इस रणनीति को प्रभावशाली तथा तुरंत अंजाम तक पहुंचाने के लिए अमेरिकी जनता के बहादुर रक्षक के रूप में आपको आवश्यक उपकरण तथा क्रियाविधि उपलब्ध कराई जाए।

हमने पहले ही अपने सैनिकों पर पूर्ववर्ती सरकार के लगाए प्रतिबंधों को हटा लिया है, जो रक्षा मंत्री तथा हमारे कमांडरों को दुश्मनों के विरुद्ध सम्पूर्ण तथा विस्तृत सैन्य कर्रवाई करने से रोकते थे। वॉशिंगटन डी. सी. से किये जानेवाले सूक्ष्म स्तरीय प्रबंधन से युद्ध नहीं जीता जा सकता। युद्धभूमि में सैनिक कमांडरों

तथा सैनिकों के वास्तविक समय में लिये जानेवाले निर्णय तथा विशेषज्ञता एवं शत्रु को पराजित करने के लिए स्पष्ट दूरदृष्टि ही युद्ध में विजय दिलाते हैं।

इसी कारण हम पूरे अफ़ग़ानिस्तान में हिंसा तथा अराजकता बोनेवाले आतंकवादियों तथा अपराधियों का नेटवर्क समाप्त करने के लिए अमेरिकी सेना का अधिकार-क्षेत्र भी बढ़ाएंगे। इन हत्यारों को मालूम होना चाहिए कि उनके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई भी क्षेत्र अमेरिकी ताकत तथा अमेरिकी हाथ के पहुंच से परे नहीं है। प्रतिशोध तेज तथा शक्तिशाली होगा।

जैसे ही हमने प्रतिबंध हटाए तथा क्षेत्र में अधिकारों का विस्तार किया, हमें आईएसआईएस को पराजित करने के सुखद परिणाम देखने मिले, जिसमें इराक़ के मोसुल की स्वतंत्रता भी शामिल है।

सत्ता में मेरे आने के बाद से, हमने इस दिशा में रिकॉर्ड सफलता प्राप्त की है। हम इन नेटवर्कों के आतंक निर्यात करने की क्षमता को नष्ट करने के लिए प्रतिबंध तथा अन्य वित्तीय एवं कानून प्रवर्तन कार्रवाईयां बढ़ाएंगे। जब अमेरिका ने अपने सैनिकों से युद्ध का वादा किया है तो ये भी सुनिश्चित करना होगा कि अपनी सेना को त्वरित, निर्णयात्मक तथा सम्पूर्ण विजय प्राप्त करने के लिए हर उपकरण उपलब्ध कराया जाए।

हम जीतने के लिए लड़ेंगे। हम विजय प्राप्त करने के लिए लड़ेंगे। अब से जीत की एक स्पष्ट परिभाषा होगी, शत्रुओं पर हमला करना, आईएसआईएस को उखाड़ फेंकना, अल क़ायदा को नेस्तनाबूद करना, तालिबान को अफ़ग़ानिस्तान पर कब्जा करने से रोकना तथा उन्हें दोबारा उभरकर अमेरिका के विरुद्ध आतंकवादी हमला करने से रोकना।

हम नेटो के अपने मित्रों तथा वैश्विक सहयोगियों से अपील करते हैं कि वो नई रणनीति को अतिरिक्त सेना तथा वित्तीय मदद में वृद्धि कर समर्थन दें। मुझे विश्वास है कि वो ऐसा करेंगे। सत्ता में आने के बाद से मैंने स्पष्ट कर दिया है कि हमारी सामूहिक रक्षा के लिए हमारे मित्रों तथा सहयोगियों को अधिक धन व्यय करना होगा, और उन्होंने ऐसा किया है।

इस संघर्ष में सबसे अधिक भार अफ़ग़ानिस्तान के अच्छे लोगों तथा उनकी साहसी सेना को उठाना होगा। जैसा अफ़ग़ानिस्तान के प्रधानमंत्री ने वादा किया है, युद्ध पर आनेवाली लागत कम करने के लिए हम आर्थिक विकास में भाग लेने जा रहे हैं।

अफ़ग़ानिस्तान अपने देश को उन्हीं शत्रुओं से बचाने तथा सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष कर रहा है, जिनसे हमें खतरा है। अफ़ग़ान सुरक्षा बल जितना मजबूत होगा, हमें उतना ही कम कार्य करना पड़ेगा। अफ़ग़ान अपने राष्ट्र की सुरक्षा तथा पुनर्निर्माण करेंगे तथा अपना भविष्य स्वयं सुनिश्चित करेंगे। हम उनकी सफलता

की कामना करते हैं।

लेकिन हम दूर-दराज के देशों में लोकतंत्र के निर्माण के लिए अमेरिकी सेना का प्रयोग नहीं करेंगे, या अन्य देशों के पुनर्निर्माण में अपनी छवि तलाशेंगे। वो दिन अब समाप्त हो गए हैं। बल्कि हम मित्रों तथा सहयोगियों के साथ अपने साझा हितों की सुरक्षा के लिए कार्य करेंगे। हम दूसरों से जीवन शैली बदलने तथा साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, जो हमारे बच्चों को बेहतर तथा सुरक्षित ज़िंदगी दें। ये सैद्धांतिक यथार्थवाद हमारे निर्णयों को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा।

सिर्फ सैनिक ताकत अफ़ग़ानिस्तान में शांति नहीं लाएगी या उस देश को आतंकवादी खतरे से नहीं उबारेगी। बल्कि दीर्घकालीन शांति प्राप्त करने के लिए रणनीतिक रूप से तैयार राजनीतिक प्रक्रिया स्थापित करने की आवश्यकता है।

अमेरिका तब तक अफ़ग़ान सरकार के साथ कार्य करता रहेगा, जब तक हम आत्मविश्वास तथा विकास देखते हैं। हमारा समर्थन असीमित नहीं है, तथा हमारा समर्थन अंधा भी नहीं है। अफ़ग़ानिस्तान सरकार को सैनिक, राजनीतिक तथा आर्थिक बोझ का अपना भार स्वयं उठाना होगा। अमेरिकी जनता वास्तविक सुधार, वास्तविक प्रगति तथा वास्तविक परिणाम देखना चाहती है। हमारी धैर्यशक्ति असीमित नहीं है। हम अपनी आंखें खोलकर रखेंगे।

20 जनवरी को मैंने जो शपथ लिया था, उसपर अमल करते हुए मैं अमेरिकी जीवन तथा अमेरिकी हितों की सुरक्षा में जुटा रहूंगा। हम किसी भी राष्ट्र के साथ अपने हित साझा कर सकते हैं, जो इस वैश्विक खतरे से लड़ने में हमारा साथ देने को तैयार है। आतंकवादी छिप सकते हैं। अमेरिका तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा, जब तक वो पूरी तरह पराजित नहीं हो जाते।

मेरे प्रशासन में सेना पर कई अरब डॉलर और खर्च होंगे। इसमें हमारे परमाणु हथियारों तथा मिसाइल सुरक्षा पर होनेवाला निवेश भी शामिल है।

हर पीढ़ी में हमने बुराईयों का सामना किया है तथा उन्हें हावी होने से रोका है। हम विजयी होते आए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कौन हैं तथा हम क्यों लड़ रहे हैं।

आज रात हम जहां इकट्ठा हुए हैं, उससे अधिक दूर नहीं है आरलिंगटन नेशनल सेमेट्री, जहां अमेरिका के सैकड़ों, हजारों महान देशभक्त हमेशा की नींद सो रहे हैं। दुनिया के किसी भी भाग की तुलना में उस पवित्र मैदान में अधिक साहस, बलिदान तथा प्रेम अवस्थित है।

11 सितम्बर 2001 के बाद कई लोगों ने अफ़ग़ानिस्तान में युद्ध में भाग लिया तथा अपनी जान न्योछावर

किये। उन्होंने एक सरल कारण के लिए अपना बलिदान दिया: वो अमेरिका को प्यार करते थे, और उसकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध थे।

अब हमें उस कारण की रक्षा करनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने अपनी जान दी। हमें अमेरिका को बाहरी दुश्मनों से बचाने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। हमें अपने घर में नागरिकों के बीच विश्वास की भावना का पुनर्संचार करना चाहिए तथा हमें इतने अधिक लोगों द्वारा चुकाए भारी कीमत का सम्मानजनक परिणाम अवश्य प्राप्त करना चाहिए।

अपने कार्यों से तथा आनेवाले महीनों में हम सभी बलिदान देनेवाले हर व्यक्ति, अपने प्रियजन को खोनेवाले हर परिवार तथा अपने महान राष्ट्र की रक्षा में रक्त बहानेवाले हर घायल का सम्मान करेंगे। अपने संकल्प से हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आपकी तथा आपके परिवार की सेवा शत्रुओं को पराजित करने एवं शांति स्थापना के काम आए।

हम अपने दिल में ताकत, आत्मा में साहस तथा आपमें से प्रत्येक पर गर्व के साथ विजय की दिशा में आगे बढ़ेंगे।

धन्यवाद। ईश्वर हमारी सेना पर आशीर्वाद बनाए रखे, तथा ईश्वर अमेरिका पर अपना आशीष बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद. (तालियां)
समाप्त

9:02 पी. एम. ईडीटी

स्रोत: द व्हाइट हाउस, प्रेस सचिव का दफ्तर, अगस्त 21, 2017

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/08/21/remarks-president-trump-strategy-afghanistan-and-south-asia